



International Journal of Advanced Academic Studies

E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAAS 2022; 4(1): 349-352
Received: 11-12-2021
Accepted: 14-01-2022

रुचि सिंह
शोध छात्रा समाजशास्त्र, शासकीय
ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय,
रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. के के सिंह
सेवानिवृत्त प्राध्यापक समाजशास्त्र,
शासकीय ठा. रणमत सिंह
महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश,
भारत

रीवा जिला में घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

रुचि सिंह एवं डॉ. के के सिंह

सारांश

इस शोध पत्र के द्वारा रीवा जिला में घरेलू महिला हिंसा में संचारक्रांति की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध में आंकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित अनुसूची का निर्माण किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल, जान से मारने से लेकर बलात्कार तक की धमकियां सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से दी जाती हैं और उन्हें शेयर भी किया जाता है। सोशल मीडिया के प्रभाव से महिलाएँ घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं। पितृसत्तात्मक समाज में एक औरत अपने साथ हुए शोषण के बारे में भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन, इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर महिलाओं ने अपने निजी मसले पर खुलकर बोलना चुना, जहां उन्हें सहयोग मिला। इस तरह से हाशिए पर रही महिलाओं को व्यक्तिगत और सांगठनिक रूप से एक दूसरे का हौसला मिला।

कूटशब्द : रीवा जिला, घरेलू महिला हिंसा, संचारक्रांति, भूमिका

1. प्रस्तावना:

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 35 प्रतिशत महिलाएं किसी ना किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि Social Media पर दुनिया की करीब 60 प्रतिशत महिलाओं के के साथ किसी प्रकार की हिंसा होती है।

भारत समेत 22 देशों की 14 हजार से ज्यादा महिलाओं के बीच किया गया है। सर्वे में शामिल महिलाओं की उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच थी। इस सर्वे के मुताबिक 39 प्रतिशत महिलाओं के साथ Online हिंसा की घटनाएं facebook पर होती हैं, जबकि Instagram पर हिंसा का शिकार होने वाली महिलाओं की संख्या 23 प्रतिशत है। 14 प्रतिशत महिलाओं के साथ Whatsapp के माध्यम से व्हस्पदम हिंसा की जाती है, जबकि Snapchat पर 10 प्रतिशत, जूपजजमत पर 9 प्रतिशत और ज्पा जवा पर 6 प्रतिशत महिलाओं के हिंसा का सामना करना पड़ता है।

Planet International नाम की एक संस्था की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 60 प्रतिशत महिलाएं Social Media पर किसी ना किसी प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं। इस वजह से 20 प्रतिशत महिलाओं को अपना Social Media Account बंद भी करना पड़ता है।

हिंसा अगर किसी Virtual Platform पर हो रही है तो भी वो असल जिंदगी में होने वाली हिंसा जितनी ही खतरनाक है। Via sat Savings-Com नाम की एक Website के सर्वे के मुताबिक इसी हिंसा और छेड़छाड़ की वजह से facebook पर 74 प्रतिशत महिलाओं को किसी ना किसी को Block करना पड़ता है। इंस्टाग्राम पर पुरुषों के मुकाबले दोगुनी महिलाएं किसी ना किसी को Block करती हैं। आप अपने घर को तो सुरक्षित बना सकते हैं, घर के आस पास ऊँची ऊँची दीवारें खड़ी कर सकते हैं, ब्ल्ट कैमरे लगा सकते हैं, लेकिन Social Media Accounts को सुरक्षित बनाने के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं हैं। Social Media Platforms का मकसद वैसे तो आपको दूसरे लोगों के करीब लाना होता है।¹

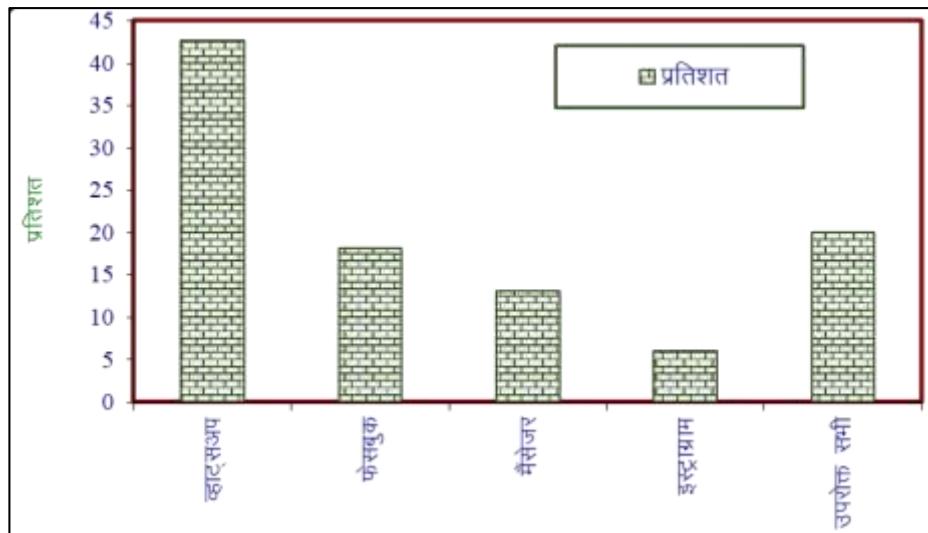
एक अंतर्राष्ट्रीय Website की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 30 वर्ष की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा व्हस्पदम हिंसा की आशंका होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक Online हिंसा की 26 प्रतिशत घटनाओं के पीछे Facebook जिम्मेदार होता है। मोबाइल फोन के जरिए Online हिंसा की 19 प्रतिशत घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि Online हिंसा के सिर्फ 33 प्रतिशत मामलों में ही Service Provider की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है और जिन मामलों की जानकारी Authorities को दी जाती है, उनमें से सिर्फ 41 प्रतिशत मामलों की ही जांच हो पाती है।

Corresponding Author:
रुचि सिंह
शोध छात्रा समाजशास्त्र, शासकीय
ठा. रणमत सिंह महाविद्यालय,
रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सारणी क्रमांक 1: सोशल मीडिया के उपयोग की स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	व्हाट्सअप	384	42.67
2.	फेसबुक	164	18.22
3.	मैंसेजर	118	13.11
4.	इस्ट्राइम	54	6.00
5.	उपरोक्त सभी	180	20.00
	योग	900	100.00

स्रोत: शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2020–21



आरेख 1: सोशल मीडिया के उपयोग की स्थिति

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 42.67 प्रतिशत व्हाट्सअप, 18.22 प्रतिशत फेसबुक, 13.11 प्रतिशत मैंसेजर, 6.00 प्रतिशत इस्ट्राइम और 20.00 प्रतिशत सभी सोशल मीडिया को चलाते हैं। आम हो या खास हर वह महिला जो भी इंटरनेट पर स्वतंत्र राय जाहिर करती है, अपने निजी कड़वे अनुभव सामने रखती है या फिर लीक से हटकर काम करती है तो रुद्धिवाद सोच के व्यक्तियों के निशाने पर आ जाती है। अपने

क्षेत्र में प्रभावी रूप से काम करने वाली महिलाओं को बेवजह सुर्खियां बनाकर ट्रोल किया जाने लगता है। महिलाओं के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल, जान से मारने से लेकर बलात्कार तक की धमकियां सोशल मीडिया पर सार्वजनिक रूप से दी जाती हैं और उन्हें शेयर भी किया जाता है। अतः स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया के प्रभाव से महिलाएँ घरेलू हिंसा एवं उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं।

सारणी क्रमांक 2: विभिन्न पूरक प्रश्नों के सापेक्ष पितृ सत्तात्मक व्यवस्था से संबंधित अभिमत

क्र.	विवरण	हाँ	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत
1.	क्या आप अपने परिवार में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं?	389	43.22	511	56.78
2.	क्या महिलाओं की वेदना/पीड़ा पर पुरुष समाज (आहे भरता / व्यथित होता है।)	422	46.89	478	53.11
3.	पितृसत्ता समाज नारी के व्यक्तित्व को ग्रहण की भाँति ग्रसित कर लेता है	636	70.67	264	29.33
4.	आर्थिक पक्ष पर पुरुषों का नियंत्रण होने से स्त्रियां स्वयं में पंगु हो जाती हैं	599	66.56	301	33.44
5.	अपने जीवन के संपूर्ण क्षेत्र में पुरुषों का हस्तक्षेप होने से उनकी अपनी इच्छा अथवा निर्णय नहीं ले पाती हैं।	605	67.22	295	32.78

स्रोत: शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर 2020–21

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 43.22 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं। 46.89 प्रतिशत महिलाओं की वेदना/पीड़ा पर पुरुष समाज आहे भरता है। 70.67 प्रतिशत प्रितसत्ता समाज नारी के व्यक्तित्व को ग्रहण की भाँति ग्रसित कर लेता है। इसी प्रकार 66.56 प्रतिशत आर्थिक पक्ष पर पुरुषों का नियंत्रण होने से स्त्रियां स्वयं में पंगु हो जाती हैं। 67.22 प्रतिशत पुरुषों का हस्तक्षेप होने से उनकी अपनी इच्छा अथवा निर्णय नहीं ले पाती हैं। शोध में इस बात का ज़िक्र किया जा चुका है कि इंटरनेट पर होने वाली हिंसा का महिलाएँ ज्यादा शिकार होती हैं। इंटरनेट ट्रोलिंग का सीधा संबंध पितृसत्ता से जुड़ा है। यह मानसिकता मानती है कि औरतें खुलकर अपनी बात न कहें। महिलाओं की अपनी कोई राय नहीं होती है, पुरुष के आदेश पर

चलना ही उनका कर्तव्य होता है। महिलाओं की आवाज को नियंत्रित करना पितृसत्ता के लिए आवश्यक होता है। महिला को अपनी पहचान हमेशा एक पुरुष के साथे में रखनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता के कारण इंटरनेट ऊंची जाति, वर्ग से आनेवाले लोगों का स्पेस बनता जा रहा है। वे महिलाएँ जो सामाजिक अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज़ मुख्यर रखती हैं, राजनीतिक रूप से स्पष्ट तौर पर अपनी बात जाहिर करती हैं उनको सोशल मीडिया पर लिंगभेद का अधिक सामना करना पड़ता है। वहीं, एलजीबीटी समुदाय के लोगों को तो बहुत ज्यादा साइबर क्राइम का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष :

अनुसंधान के परिणामों से प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार हैं—

- शोध क्षेत्र के 42.67 प्रतिशत व्हाट्सअप, 18.22 प्रतिशत फेसबुक, 13.11 प्रतिशत मैसेजर, 6.00 प्रतिशत इस्ट्राग्राम और 20.00 प्रतिशत सभी सोशल मीडिया को चलाते हैं।
- शोध क्षेत्र के 43.22 प्रतिशत उत्तरदाता अपने परिवार में लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते हैं। 46.89 प्रतिशत महिलाओं की वेदना/पीड़ा पर पुरुष समाज आहे भरता है। 70.67 प्रतिशत प्रितसत्ता समाज नारी के व्यक्तित्व को ग्रहण की भाँति ग्रसित कर लेता है। इसी प्रकार 66.56 प्रतिशत आर्थिक पक्ष पर पुरुषों का नियंत्रण होने से स्त्रियां स्वयं में पंगु हो जाती हैं। 67.22 प्रतिशत पुरुषों का हस्तक्षेप होने से उनकी अपनी इच्छा अथवा निर्णय नहीं ले पाती हैं।
- पितृसत्तात्मक समाज में एक औरत अपने साथ हुए शोषण के बारे में भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन, इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया पर महिलाओं ने अपने निजी मसले पर खुलकर बोलना चुना, जहां उन्हें सहयोग मिला। इस तरह से हांशिए पर रही महिलाओं को व्यक्तिगत और सांगठनिक रूप से एक दूसरे का हौसला मिला।

संदर्भ

1. DNA Analysis: सोशल मीडिया पर कितने 'असामाजिक लोग', ऐसे करते हैं महिलाओं का उत्पीड़नए Zee News Desk, Last Updated: Oct 07, 2020, 09:45 AM IST.
2. आशारानी छोरा. (भारतीय समाज में स्त्री, नटराज प्रकाशन, दिल्ली, 2005, पेज नं. 40).
3. आहूजा, राम, रावत प्रेमण सामाजिक समस्याए, महिला के विरुद्ध हिंसा, तृतीय संस्करण, रावत पब्लिकेशन, 2016, 222–234.
4. ममता. घरेलू हिंसा, अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता, रिगल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010, पृ. 77–81.
5. शर्मा, मंजू. 'नारी शोषण और मानवाधिकार' प्रकाशन राज पब्लिशिंग हाउस 44, परनामी मन्दिर जयपुर, प्रथम संस्करण, 2008.
6. शर्मा, पूजा. महिलाएँ एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2012 पृ. 64–65.
7. शर्मा, जी.एल. सामाजिक मुद्दे, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा : घरेलू हिंसा (निरोधक) अधिनियम, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली, बंगलौर पेज, 2015, 220–221.